the problem of Urban Transport. Low cost measures like prohibition of on-street parking, segregation of fast and slow moving traffic, flexible laning, introduction of traffic-free zones, etc. are implemented by, State Governments. Depending on the traffic load, proposals for introduction of Light Rail Transit System/Mass Rapid Transit System have been initiated by the State Governments. Such projects, however, are highly capital intensive in nature and it is not possible to finance such projects through budgetary means of Central/State Governments alone. Therefore, efforts are made to seek soft loan assistance from various international aid agencies for such projects. Delhi MRTS Project is one such example for which soft loan is being provided by OEC (Japan).

केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों की आवास समस्या

1071. **श्री शमशेर सिंह सुरजेवाला:** क्या शहरी कार्य और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि देश में, विशेषकर दिल्ली में केन्द्र सरकार के कर्मचारियों को आवास की गंभीर समस्या का सामना करना पड़ा रहा है;

(ख) विभिन्न श्रेणियों स्थानवार कितने फ्लैट खाली पड़े हैं तथा इसके क्या कारण हैं;

(ग) महानगरों में केन्द्र सरकार के कर्मचारियों के लिए अनुमानित कितने मकानों की कमी है;

(घ) आवास समस्या को हल करने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं;

(ङ) दिल्ली तथा अन्य महानगरों में केन्द्र सरकार के कर्मचारियों के संबंध में आवास की श्रेणीवार वर्तमान स्थिति का ब्यौरा क्या है; और

(च) अगले तीन वर्षों के दौरान दिल्ली तथा देश के अन्य नगरों में सरकार द्वारा कितने मकान बनाने का विचार है और इस प्रयोजन हेतु कितनी धनराशि निर्धारित की गई है?

शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय के राज्य मंत्री (डा० यू० वेंकटेश्वरलू): (क) जी, हां।

(ख) सेवा निवृत्त, स्थानांतरण, मृत्यु, निम्न श्रेणी वास से उच्च श्रेणी वास में परिवर्तन आदि कारणों से प्रतिदिन आबंटितियों द्वारा कई वास खाली किये जाते हैं। बाद में ये आवास पात्र व्यक्तियों को आबंटित कर दिये जाते हैं और चूंकि यह एक सतत प्रक्रिया है, अतः निश्चित समय सीमा में खाली पड़े मकानों की संख्या बताना संभव नहीं है।

(ग) से (च) चार महानगरों के विभिन्न श्रेणियों/टाइप के आवास स्टॉक और रिहायशी वास की कमी और उपलब्धता दर्शाने वाला विवरण नीचे दिया गया है।

नौवीं योजना में वर्ष 1997-98 से प्रारम्भ होने वाले प्रस्तावों पर सामान्य पूल रिहायशी वास स्कीम के लिए 500 करोड़ रु० की राशि निर्दिष्ट करने का प्रस्ताव है और इस अवधि के दौरान भारत के विभिन्न नगरों में लगभग 10,000 आवास बनाये जाने का प्रस्ताव है, जिसमें से 2000 दिल्ली में बनाये जायेंगे। इन वर्षों के लिए प्रथम तीन वर्षों में निर्माण कार्य योजना परिव्यय के आधार पर होगा।

विवरण

श्रेणी	दिल्ली 1-7-97 की स्थिति के अनुसार		मुम्बई/न्यू मुम्बई 1-7-97 की स्थिति के अनुसार		कलकत्ता 31-3-97 की स्थिति के अनुसार		मद्रास 31-3-97 की स्थिति के अनुसार	
	उपलब्धता	कमी	उपलब्धता	कमी	उपलब्धता	कमी	उपलब्धता	कमी
I	16488	8351	3271	1131	1760	778	450	342
II	23204	15288	3702	2486	2444	2358	880	990
III	16235	15053	1323	880	1352	582	435	1087
IV	5001	4054	569	401	186	226	326	47
विशेष	484	1166	28	177	—	—	—	—
V	1848	1640	228	221	117	262	85	64
VI	586	691	90	43	101	16	16	7
VII	108	117	—	—	—	—	—	—
VIII	113	138	—	—	—	—	—	—